भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 91

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया जाना है)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के मसौदे की वर्तमान स्थिति

91. डॉ. शशि थरूरः

श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के मसौदे की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ख) पूर्व-विधायी परामर्श नीति के अंतर्गत परामर्श किए गए हितधारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मसौदा विधेयक को आगे के परामर्श के लिए जारी करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा नवाचार को बढ़ावा देने और बड़े डिजिटल उद्यमों के प्रभाव को विनियमित करने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार से सिफारिश की है कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के प्रस्तावित मसौदे में पूर्व-प्रावधान को इस स्तर पर कानून से बाहर रखा जाए;

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्तावित पूर्व-प्रावधान विनियमन के अंतर्गत छोटे उद्यमों, विशेषकर स्टार्ट-अप्स पर संभावित प्रभावों का आकलन किया है और साथ ही अप्रत्याशित परिणामों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) राजस्थान और देश में प्रमुख तकनीकी फर्मों की चिंताओं को कम करने के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): "बिग-टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यप्रणालियों" विषय पर अपनी तिरपनवीं रिपोर्ट में संबंधी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर एक समिति का गठन किया।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की पूर्व-विधायी परामर्श नीति (पीएलसीपी) के अनुरूप मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) पर परामर्श निम्नानुसार आयोजित किए गए थे:-

- मार्च 2023 के दौरान, सीडीसीएल ने प्रस्तावित कानून से प्रभावित होने वाली संस्थाओं और हितधारकों, जिसमें उद्योग संघ, घरेलू और विदेशी डिजिटल उद्यम और थिंक-टैंक आदि शामिल हैं, के साथ परामर्श किया। हितधारकों की सूची अनुलग्नक-I पर दी गई है।

- परामर्श के बाद, सीडीसीएल ने फरवरी 2024 में एक मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर समिति की रिपोर्ट के साथ मसौदा डीसीबी को 12 मार्च से 15 मई, 2024 तक ई-परामर्श मोड के तहत एमसीए वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। 100 से अधिक हितधारकों, जिनमें कानूनी पेशेवर, उद्योग संघ, नागरिक समाज संगठन और भारत में डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने वाले घरेलू एवं विदेशी डिजिटल उद्यम शामिल हैं, ने अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कीं। हितधारकों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

- इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 18.06.2024 से 20.06.2024 के बीच हितधारक परिचर्चाओं का आयोजन किया। टिप्पणियों/इनपुट की प्रतीक्षा है, सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों/इनपुट/टिप्पणियों की जांच की गई है।

प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों/इनपुट के आधार पर, यह महसूस किया गया है कि बाजार अध्ययन के माध्यम से साक्ष्य-आधारित आधार की आवश्यकता है ताकि पूर्व-नियमन के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर यह देखते हुए विचार किया जा सके कि यह वैश्विक स्तर पर आरम्भिक कार्यान्वयन चरणों में है।

(ङ) और (च): सीडीसीएल ने प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श किया और डिजिटल सेवाओं के नियमन के लिए घरेलू कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय नियामक कार्यप्रणालियों दोनों की जांच की। इसके बाद, डीसीबी का मसौदे तैयार करने के दौरान, छोटे व्यवसायों, थिंक टैंकों और प्रमुख तकनीकी फर्मों के व्यापार और उद्योग संघों के कई प्रतिनिधियों के साथ उनके विचार/टिप्पणियां लेने के लिए परामर्श किया गया।

सभी हितधारकों से सुझाव/इन्पुट्स/टिप्पणियों की जांच कर ली गई है।

*****

अनुलग्नक- I

1. अमेजन
2. एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3. बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और स्विगी
4. सेंटर फॉर द डिजिटल फ्यूचर
5. फिल्पकार्ट
6. गूगल
7. इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन
8. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
9. मेटा (फेसबुक)
10. ओयो
11. उबर
12. यूएसआईबीसी
13. ज़ोमैटो
14. अल इंडिया गेमिंग महासंघ
15. एलाएंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन
16. अर्थ ग्लोबल
17. एशिया यात्रा प्रौद्योगिकी उद्योग संघ
18. एजेडबी एंड पार्टनर्स
19. अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ
20. डिजिटल समाचार प्रकाशक संघ
21. एस्या केंद्र
22. भारतीय होटल एवं रेस्तरां संघों का महासंघ
23. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद
24. मेकमाईट्रिप
25. भारतीय समाचार पत्र संघ
26. भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ
27. नैसकॉम
28. पेटीएम
29. ट्विटर.

<u>अनुलग्नक- II</u>

क्र. सं.	हितधारक का नाम
1.	नीति आयोग
2.	फर्स्ट इंडिया
3.	सीसीएओआई
4.	स्विगी
5.	अमेरिकन बार एसोसिएशन
6.	ई-गेमिंग फेडरेशन
7.	यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी)
8.	भारत सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए**)**
9.	स्काईस्कैनर
10.	एसोचैम
11.	अमेरिका-भारत कार्यनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ)
12.	मैच समूह
13.	भारतीय डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम के संस्थापक और निवेशक
14.	भारतीय शासन और नीति परियोजना (आईजीएपी**)**
15.	प्ले गेम्स24*7 प्राइवेट लिमिटेड
16.	नैसकॉम
17.	लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेज इंडिया
18.	तकनीकी स्वतंत्रता
19.	अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ (एआईजीएफ)
20.	इंडिया रेगुलेटरी प्रैक्टिसेज ग्रुप एलएलपी (आईआरपीजी)
21.	मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक.
22.	सिविस
23.	शिल्पी भट्टाचार्य**,** प्रोफेसर**,** जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस)
24.	प्रतिस्पर्धा कानून और अर्थशास्त्र केंद्र (सीसीएलई)
25.	अमेज़न इंडिया
26.	इंडिया मार्ट

27.	एयरटेल
28.	एक्सेस नाउ
29.	अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन (आईबीए)
30.	ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ)
31.	भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) और भारतीय डिजिटल मीडिया उद्योग फाउंडेशन (आईडीएमआईएफ)
32.	ऐप निष्पक्षता गठबंधन (सीएएफ)
33.	ओला इलेक्ट्रिक
34.	द डायलॉग
35.	इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ)
36.	अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं अर्थशास्त्र केंद्र
37.	मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एमपीए)
38.	भारतीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी)
39.	पीआरएस विधायी अनुसंधान
40.	ईबीसी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड और एससीसी ऑनलाइन
41.	मेकमाईट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
42.	डिजिटल इंडिया फाउंडेशन का गठबंधन (एडीआईएफ)
43.	एमएआईटी
44.	टाटा डिजिटल
45.	प्रगतिशील नीति संस्थान (पीपीआई)
46.	फोनपे प्राइवेट लिमिटेड
47.	ट्राइलीगल
48.	नेटफ्लिक्स
49.	ज़ोमैटो
50.	गूगल
51.	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल
52.	भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई)
53.	इंडिया टेक.ऑर्ग
54.	इंडस्लाव
55.	डिजिटल समाचार प्रकाशक संघ (डीएनपीए)
56.	सॉफ्टवेयर स्वतंत्रता कानून केंद्र (एसएफएलसी)
57.	इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई)
58.	हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
59.	कोआन सलाहकार समूह
60.	ईएसवाईए केंद्र
61.	प्रोसस
62.	कॉट्स इंटरनेशनल

63.	डीपस्ट्रैट प्राइवेट लिमिटेड
64.	फिक्की
65.	सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन (आईटीआईएफ)
66.	(एसीटी) ऐप एसोसिएशन
67.	अनुपम सांघी एंड एसोसिएट्स (एएसए)
68.	एशिया इंटरनेट गठबंधन (एआईसी)
69.	एशिया ट्रैवल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन (एटीटीआईए**)**
70.	कंप्यूटर और संचार उद्योग संघ (सीसीआईए**)**
71.	भारतीय संगीत उद्योग (आईएमआई)
72.	माइक्रोसॉफ्ट
73.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
74.	डीएमडी एडवोकेट्स
75.	अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाइटी (एआईसीएएस)
76.	कम्पास लेक्सिकॉन के अर्थशास्त्री (जस्टिन कूम्ब्स**,** कादम्बरी प्रसाद**,** नेहा जॉर्जी) और एफटीआई कंसल्टिंग (अविनाश मेहरोत्रा**,** जिंसी फ्रांसिस)
77.	इंटरनेट और समाज केंद्र (सीआईएस)
78.	सिद्धार्थ चौहान**,** एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट डीन**,** जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल**,** ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी
79.	बीटीजी अद्वय
80.	ऋषभ बेली और आईटी फॉर चेंज
81.	डीएसके लीगल- अधिवक्ता और सॉलिसिटर
82.	ट्रूकॉलर
83.	डायनामिक कॉम्पिटिशन इनिशिएटिव (डीसीआई)
84.	टचस्टोन पार्टनर्स
85.	आर्थिक कानून कार्यप्रणाली (ईएलपी)
86.	भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई)
87.	उबर
88.	नबीन जैन
89.	रुचिका गंभीर (शोधकर्ता)
90.	अभिवर्धन (इंडिक पेसिफिक लीगल रिसर्च)
91.	रश्मि बरनवाल (पेशेवर)
92.	अभिषेक मुरुकाटे
93.	विकास कथूरिया (शोधकर्ता)
94.	जयश्री चंद्रा (पेशेवर)
95.	अमेय कंटक (शोधकर्ता)
96.	इकरा जबीन अंसारी **(**एलटीआईएम**)**
97.	पंखुड़ी खंडेलवाल (डायनामिन कॉम्पिटिशन इनिशिएटिव)
98.	ब्लेज़ फर्नांडीस (भारतीय संगीत उद्योग)

99.	जसलीन कौर(पेशेवर)
100.	मुरुगावेल जानकीरमन (मैट्रिमोनी.कॉम)
101.	अजय कामथ (कामथ लीगल)
102.	आकांक्षा जी (शोधकर्ता)
103.	नील भूटानी (डेवेस्को एलएलपी)
104.	विवेक अग्रवाल
105.	एमचैम इंडिया
106.	पीपल ग्रुप/शादी.कॉम और अन्य